प्यासे पंछियों को पानी पिलाएं आओ इस आदत को संस्कार बनाएं...

पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं...

दिव्य आकाश

कोरबा से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रथम बहुरंगी साप्ताहिक अखबार

वर्ष -17, अंक - 9 | अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी, विक्रम संवत् 2083, कोरबा, शुक्रवार, दिनांक 05 से 11 जून 2026 | पृष्ठ - 8, रू. 3:00

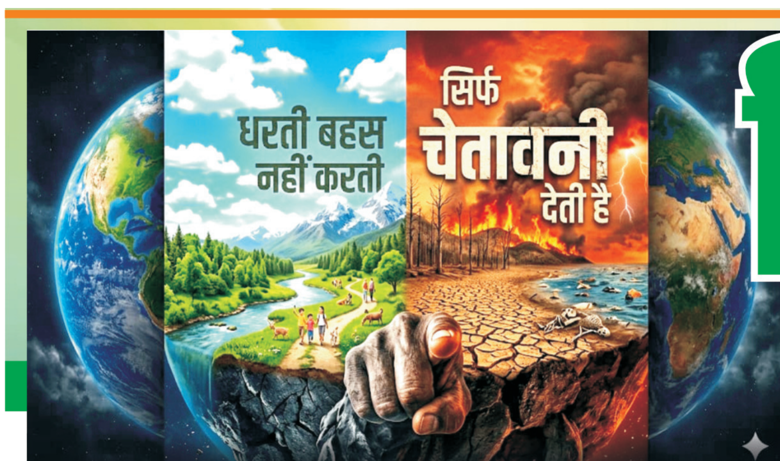

विश्व पर्यावरण दिवस

मनुष्य जाति की गलती का खामियाजा सभी चर-अचर प्राणी भुगत रहा है। मनुष्य चांद पर पहुंच गया और उसकी आकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वह प्रकृति को ही चुनौती देने लगा। इस चुनौती का प्रकृति ने इस तरह बदला लिया कि मनुष्य जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ने लगा। प्राकृतिक आपदा इतनी बढ़ गई कि उसकी भरपाई करने में मनुष्य को कई साल लग जाते हैं। प्रकृति से छेड़-छाड़ करोगे तो भुगतोगे ही। प्रकृति बहस नहीं करती, चेतावनी देती है।

यदि प्रकृति की इस मौन चेतावनी से मनुष्य जाति यदि सुधर जाती है, तो उसका ही भला होगा। प्रकृति की चेतावनी का असर भी साफ दिखने लगा है, कि कम से कम अब प्रकृति को बचाने के लिए मनुष्य अब चिंतन तो करने लगा है और स्वच्छ, सुंदर तथा प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए उपाय करने लगा है। प्रकृति से जुड़कर ही हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं, इसलिए आज से ही प्रकृति संरक्षण एवं संवर्धन की आदतों को अपनी कार्यशैली में अपनाएं... फोटो एआई जनरेटेड

विस्तृत आलेख- 04 पेज पर अवश्य पढ़ें।

केबिनेट की बैठक 09 को

रायपुर (दिव्य आकाश)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद् (केबिनेट) की बैठक मंगलवार, 09 जून को सवेरे 11.00 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी।

शिमला में भारी बारिश, ऊंची चोटियों पर हिमपात

शिमला, एजेंसी। हिमाचल के कई भागों में आज तेज बारिश और अधिक ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ। शिमला में दोपहर पौने एक बजे के बाद डेढ़ घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे शहर की सड़कें पानी के तालाब में तब्दील हो गई। भारी बारिश के बाद टूरिस्ट के भरा रिज पूरी तरह खाली हो गया। शिमला में कुछ ही देर में 32.8 मिलीमीटर बारिश हुई।

एक पेड़ माँ के नाम को जन आंदोलन बनाएं- राज्यपाल

रायपुर (दिव्य आकाश)।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पर्यावरणीय संकट और भविष्य में संभावित जल संकट को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। राज्यपाल ने कहा कि जल और जंगल एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि पानी रहेगा तो पेड़-पौधे सुरक्षित रहेंगे और यदि पेड़ रहेंगे तो जल स्रोतों का संरक्षण संभव होगा।

राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें।

राज्यपाल ने कहा कि देश और दुनिया के अनेक क्षेत्रों में जल स्रोत लगातार घट रहे हैं। भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है। वर्षा जल संचयन, जल का विवेकपूर्ण उपयोग, तालाबों और जल स्रोतों का संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे प्रयास सामूहिक रूप से किए जाएं तो आने वाले वर्षों में जल संकट की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका लोक भवन तथा नया रायपुर स्थित निर्माणाधीन लोक भवन परिसर में वृक्षारोपण करेंगे। राज्यपाल श्री डेका ने लोक भवन के कर्मचारियों को पौधे भेंट किए तथा उन्हें अपने घरों एवं आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।

मयंक पाण्डेय ने पौधरोपण की विस्तृत जानकारी दी

राज्यपाल रमेन डेका से लोकभवन में रायपुर वन वृत्त के संभागीय वन अधिकारी मयंक पाण्डेय ने 5 जून को आयोजित होने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वन विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस तक सीमित न रहकर सतत सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

05 जून विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई...

पेड़ पौधे लगाएंगे हम,
धरती को हरा-भरा बनाएंगे हम।
इस मानसून एक पेड़
माँ के नाम अवश्य लगाएं और
माँ भारती का हरित श्रृंगार करें।

चन्द्रमा सिंह राजपूत
रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, वरिष्ठ भाजपा नेता कोरबा
वरिष्ठ सदस्य - पूर्वांचल विकास समिति, वरिष्ठ सदस्य - राजपूत क्षत्रीय समाज
वरिष्ठ समाज सेवी कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.), 99261-98100

प्रदेश में 2.50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

रायपुर (दिव्य आकाश)।

पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को सुदृढ़ करना आधुनिक युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही पर्यावरण-हितैषी नीतियों के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर साफ दिखने लगे हैं। देश में हरित आवरण (ग्रीन कवर) को बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP), मनरेगा और नगर वन योजना जैसी शासकीय योजनाओं के बेहतर समन्वय से हर साल वृक्षारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है।

इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन संवर्धन और हरियाली को बढ़ाने के लिए विगत वर्षों से लगातार वृहद पैमाने पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। आज 05 जून 2026 को विश्व वानिकी दिवस के पावन अवसर पर इस वर्ष के भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है।

वर्ष 2026: संकल्प, लक्ष्य और अभूतपूर्व तैयारियां

भारत सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा चालू वर्ष (वर्षाऋतु 2026) के लिए राज्य को 2 करोड़ 50 लाख पौधों के रोपण एवं वितरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त हुआ है। राज्य शासन ने इस लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल करने के लिए सभी वनमंडलों में व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पूरे अभियान को सितंबर 2026 तक पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के 'मेरी लाईफ' (Meri LiFE) पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।

योजनावार कुल रोपण: कुल 13,030 हेक्टेयर और 14.50 किलोमीटर क्षेत्र में 1 करोड़ 67 लाख 78 हजार पौधों का रोपण किया गया। इसमें विभागीय योजनाएं (26.21 लाख), मनरेगा (11,941), कैम्पा (18.49 लाख), अन्य योजनाएं (67.92 लाख) और छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (55 लाख) का सराहनीय योगदान रहा।

जन-साधारण को हरियाली से जोड़ने के लिए 59 लाख 04 हजार पौधों का वितरण किया गया।

सीजेआई बोले- शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला

गांवों में समुदाय अब भी जीवन का केंद्र, हमें जीवन को बैलेंस करना सीखना होगा

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने लिखा- शहरों में भीड़ के बावजूद मनुष्य अकेला रह जाता है, जबकि गांव में समुदाय संस्कृति का आधार हैं। भारत के विकास की चर्चा महानगरों, उद्योगों, तकनीक और आधुनिक संरचना के संदर्भ में की जाती है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और तीव्र आर्थिक गतिविधियां प्रगति का प्रतीक मानी जाती हैं, किंतु इस विकास यात्रा के बीच महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है- क्या हम अनजाने में गांवों की मूल आत्मा को खोते जा रहे हैं? क्या विकास का अर्थ यह होना चाहिए कि गांव धीरे-धीरे शहर का रूप ले लें? अथवा हमें ऐसा भारत निर्मित करना चाहिए, जहां गांव अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक आत्मीयता और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से भी सम्पन्न हों? यह पूरे भारत के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है, परंतु हरियाणा के गांवों का उल्लेख इसलिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वहां आज भी सामुदायिक जीवन, श्रम संस्कृति आत्मसम्मान और सामाजिक सहभागिता की परंपरा जीवंत है।

आज मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत बोर्ड परीक्षा के टॉप-10 छात्रों का होगा सम्मान

रायपुर (दिव्य आकाश)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शुक्रवार 5 जून को दोपहर 2.30 बजे न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप-10 में स्थान बनाने वाले पंजीकृत श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। इस गरिमामय अवसर पर श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन एवं छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ - योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक मेधावी छात्र को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उच्च शिक्षा और आवागमन को सुगम बनाने के लिए दोपहिया वाहन क्रय करने हेतु 1 लाख रुपये का विशेष अनुदान देने का भी प्रावधान है। इस प्रकार प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को कुल रुपये 2,00,000/- का चेक वितरण कर लाभान्वित किया जाना है।

पात्रता एवं नियम- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं। हितग्राही श्रमिक का श्रम कल्याण मंडल में कम से कम 90 दिन पूर्व से पंजीकृत होना आवश्यक है। यह वार्षिक प्रोत्साहन राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल प्रथम दो बच्चों को ही देय होगी। इस योजना का लाभ एक शैक्षणिक वर्ष में केवल एक बार ही लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह कल्याणकारी योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए एक बड़ा संबल प्रदान कर रही है।

चैतमा रेंज में 87 हजार पौधों का होगा रोपण एवं वितरण

कोरबा/चैतमा (दिव्य आकाश)।

कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत वनपरिक्षेत्र चैतमा में इस मानसून करीब 87 हजार पौधों का रोपण एवं वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। वनपरिक्षेत्राधिकारी दिनेश कुर्रे ने बताया कि वनमण्डलाधिकारी निशांत कुमार के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में सभी वनपरिक्षेत्रों को इस मानसून पौधरोपण एवं वितरण का लक्ष्य दिया गया है। इसी कड़ी में वनपरिक्षेत्र चैतमा में करीब 87 हजार पौधों का रोपण एवं वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। वृक्ष संपदा योजना के तहत 45 हजार, कैम्पा मद के तहत 21 हजार पौधों का रोपण किया जाएगा, वहीं खेत-खलिहानों, स्कूल परिसरों एवं अन्य भवनों के परिसरों में पौधरोपण के लिए 20 हजार पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। सूत्रों के अनुसार कोरबा एवं कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत 10 लाख से अधिक पौधरोपण एवं पौध वितरण का लक्ष्य रखा गया है। 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ पौधरोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले से 01 भारतीय की मौत, 63 घायल

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन, एजेंसी। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया है। कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को यह वीडियो जारी किया। वीडियो में एक ड्रोन एयरपोर्ट की छत से टकराता दिखाई दे रहा है। टक्कर होते ही ड्रोन के टुकड़े बिखर जाते हैं और आसपास नुकसान होता है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई, जबकि 63 लोग घायल हुए हैं। कुवैत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कई घायलों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। हमले से एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को काफी नुकसान पहुंचा। सुरक्षा कारणों से कुछ समय के लिए एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन भी रोक दिया गया था। ईरान ने कुवैत और बहरीन को चेतावनी दी: तेहरान ने कहा कि अगर किसी देश की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हुआ तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। ट्रम्प ने कहा- ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त मानी।

नपा दीपका में उपचुनाव:वार्ड 15 के पार्षद चुनाव में भाजपा की जीत, ऋषि सिदार बने पार्षद

कोरबा/दीपका (दिव्य आकाश)।

गोपाल मोदी के नेतृत्व में भाजपा का विजय अभियान जारी, उपचुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ

नगर पालिका परिषद दीपका के वार्ड क्रमांक 15 में संपन्न उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक एवं प्रचंड विजय दर्ज करते हुए एक बार फिर जनता का विश्वास हासिल किया है। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी ऋषि सिदार ने भारी जनसमर्थन प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को बड़े मतों के अंतर से पराजित करते हुए पार्षद पद पर शानदार जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम घोषित होते ही पूरे वार्ड में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल बन गया। कार्यकर्ताओं ने फटाखे फोड़कर, एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर तथा भारत माता और भाजपा के जयघोष के साथ विजय का जश्न मनाया।

गौरतलब है कि भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में संगठन लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में भी भाजपा ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। वार्ड क्रमांक 15 के उपचुनाव में मिली यह प्रचंड जीत संगठन की बढ़ती मजबूती और जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण मानी जा रही है। भाजपा नेताओं ने वार्ड की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए विकास एवं जनसेवा के कार्यों को और अधिक गति प्रदान करेगी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि वार्ड क्रमांक 15 के उपचुनाव में मिली यह ऐतिहासिक जीत संगठन की एकजुटता, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। चुनाव अभियान के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने घर-घर पहुंचकर व्यापक जनसंपर्क किया।

SECL की खदानों में ठेका श्रमिकों का बड़ा शोषण, राष्ट्रीय कालरी वर्कर्स फेडरेशन ने मुख्य श्रम आयुक्त से की शिकायत

कोरबा/नई दिल्ली (दिव्य आकाश)।

राष्ट्रीय कालरी वर्कर्स फेडरेशन (RCWF) ने कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) और उसके अधीन काम करने वाले दर्जनों निजी ठेकेदारों के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन ने मुख्य श्रम आयुक्त-भारत सरकार के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराकर SECL की विभिन्न भूमिगत (Underground) और खुली (Opencast) खदानों में चल रहे गंभीर श्रम उल्लंघनों और श्रमिकों के शोषण को उजागर किया है ।

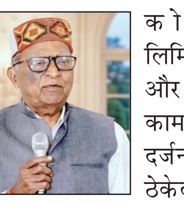

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि SECL प्रबंधन और निजी ठेकेदार केंद्र सरकार के व्यवसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 (OSHW Code 2020) तथा मजदूरी संहिता (Code on Wages) 2019 की धज्जियां उड़ा रहे हैं ।

मुख्य आरोप-

मुख्य गतिविधियों (Core Activities) में अवैध तैनाती:- OSHW कोड 2020 की धारा 57 के तहत किसी भी प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यों में ठेका श्रमिकों को रखना सख्त प्रतिबंधित है इसके बावजूद SECL द्वारा कोयला निष्कर्षण, कोयला काटना, लोडिंग, छत को सहारा देना (Roof support) और भारी अर्थ-मूविंग मशीनरी चलाने जैसे अत्यधिक जोखिम भरे और मुख्य कार्यों में बड़े पैमाने पर ठेका श्रमिक लगाए जा रहे हैं ।

30 साल तक के लंबे और संदेहास्पद अनुबंध:- टेक्नो ब्लास्ट माइनिंग, जॉय माइनिंग चेन्नई, राधा इंजीनियरिंग वर्क्स (CREW), सिनचैती, नीलकंठ इन्फ्रा सहित कई कंपनियों को 6 से लेकर 30 वर्षों तक के दीर्घकालिक ठेके दिए गए हैं, RCWF का कहना है कि इतने लंबे समय के अनुबंध यह साबित करते हैं कि यह कार्य स्थायी (Permanent & Perennial) प्रकृति का है जिसे छुपाने के लिए कानून के साथ धोखाधड़ी (Sham Contract) की जा रही है ।

नियुक्ति पत्र से वंचित और कम मजदूरी:- OSHW कोड की धारा 6 का उल्लंघन करते हुए हजारों श्रमिकों को कोई नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) नहीं दिया गया है जिससे उनका रोजगार असुरक्षित है साथ ही धारा 8 और वेज कोड 2019 का उल्लंघन कर नियमित कर्मचारियों के मुकाबले इन ठेका श्रमिकों को बेहद कम मजदूरी दी जा रही है ।

सभी श्रमिकों को सीधे नियमित करने की मांग

सर्वोच्च न्यायालय के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) बनाम नेशनल यूनियन वॉटरफ्रंट वर्कर्स (2001) के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए RCWF के नेता भागवत प्रसाद दुबे ने स्पष्ट किया है कि जहां कानून का उल्लंघन करके मुख्य गतिविधियों में ठेका श्रमिक लगाए जाते हैं वहां वह अनुबंध कानूनी रूप से शून्य (Nullity) माना जाता है। ऐसे में ये सभी श्रमिक स्वतः ही मुख्य नियोक्ता (SECL) के सीधे कर्मचारी माने जाते हैं हमारी मांग है कि इन सभी श्रमिकों को उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वेतन संरक्षण वरिष्ठता पीएफ ग्रेच्युटी और चिकित्सा लाभ के साथ SECL का नियमित कर्मचारी बनाया जाए ।

मुख्य श्रम आयुक्त से की गई मुख्य मांग

SECL खदानों की मुख्य गतिविधियों में चल रहे ठेका श्रम की तुरंत गहन जांच और निरीक्षण कराया जाए OSHW कोड की धारा 104 के तहत दोषी SECL प्रबंधन और ठेकेदारों के खिलाफ 2 साल तक की कैद और रू. 5 लाख तक के जुर्माने की दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर ठेका श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों के बराबर मजदूरी और पुराने बकाए (Arrears) का भुगतान सुनिश्चित किया जाए मुख्य गतिविधियों के लिए चल रहे मौजूदा ठेकों के नवीनीकरण और नए टेंडरों पर तुरंत रोक लगाई जाए ।

इस शिकायत की प्रतियां केंद्रीय श्रम सचिव भारत सरकार, अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड, सीएमडी SECL बिलासपुर, आर.एल.सी. बिलासपुर और डी.जी.एम.एस. धनबाद को भी आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर शोषण पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो श्रमिक हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को और उग्र किया जाएगा ।

मजदूर फांसी पर झूला

कोरबा/उरगा। उरगा थाना क्षेत्र स्थित पकरिया गांव में गुरुवार को एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 33 वर्षीय राम प्रसाद पटेल ने अपने घर के आंगन में पेड़ से लटककर जान दे दी। घटना के समय उन्होंने अपनी पत्नी को तालाब में नहाने के लिए भेजा था। जानकारी के अनुसार, राम प्रसाद पटेल और उनकी पत्नी दोनों गांव के पास स्थित फ्लाई ऐश फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। गुरुवार दोपहर काम खत्म करने के बाद वे घर लौटे। घर पहुंचने पर राम प्रसाद ने अपनी पत्नी को तालाब में स्नान के लिए भेज दिया। पत्नी के जाते ही उन्होंने आंगन में लगे पेड़ पर फांसी लगा ली। नहाने के बाद पत्नी जब घर लौटी तो पति को फंदे पर लटका देखा तो वह चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। परिजनों ने तुरंत राम प्रसाद को फंदे से उतारा और जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राम प्रसाद पटेल के पिता का नाम रूप सिंह पटेल है, जो खेती-किसानी करते हैं। राम प्रसाद के दो छोटे बच्चे हैं, जिनमें 8 साल की बेटी और 3 साल का बेटा शामिल है।

आईटीआई करतला एवं पोंड़ी-उपरोड़ा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 15 जून तक आमंत्रित

कोरबा (दिव्य आकाश)। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था करतला एवं पोंड़ी-उपरोड़ा में प्रवेश सत्र 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। इच्छुक अभ्यर्थी संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के विभागीय वेबसाइट cgiti.admissions.nic.in में जाकर विवरणिका का भली-भांती अवलोकन कर पात्रतानुसार आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित संस्था से संपर्क किया जा सकता है।

समीक्षा बैठक आज

कोरबा। कलेक्टर की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कार्यों की विभागीय मासिक समीक्षा बैठक 05 जून को शाम 04 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आहुत की गई है। बैठक में सर्व संबंधितों को उपस्थित होने कहा गया है।

जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के नेतृत्व में संगठन को मिल रही नई दिशा, भिलाई बाजार मंडल की कार्यसमिति बैठक संपन्न

भाजपा भिलाई बाजार मंडल की कार्यसमिति एवं मासिक बैठक संपन्न, बूथ सशक्तिकरण पर विशेष जोर

कोरबा (दिव्य आकाश)।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार एवं जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के उद्देश्य से भाजपा भिलाई बाजार मंडल द्वारा रलिया स्थित मंडल कार्यालय में मंडल कार्यसमिति एवं मासिक बैठक का सफल आयोजन किया गया। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम् के साथ हुआ। मंडल अध्यक्ष दिनेश राठौर ने स्वागत उद्बोधन देते हुए उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। बैठक में संगठनात्मक विषयों, बूथ सशक्तिकरण, संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं से संगठन की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया।

भाजपा कार्यकर्ता संगठन की शक्ति, जनता के बीच बढ़ाएं संपर्क : शैलेंद्र यादव

वहीं मंडल सह प्रभारी शैलेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की विचारधारा, रीति-नीति एवं जनसेवा के कार्यों को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित और समाजहित को सर्वोपरि मानते हुए संगठन को मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए।

कार्यकर्ताओं का समर्पण, परिश्रम और सक्रियता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं - दिनेश राठौर

मंडल अध्यक्ष दिनेश राठौर ने कहा कि कि कार्यकर्ताओं का समर्पण, परिश्रम और सक्रियता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं साथ ही उन्होंने संगठन हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

विनोद कुमार यादव ने रखा राजनीतिक प्रस्ताव, कार्यकर्ताओं ने हाथ उठाकर किया समर्थन

मंडल प्रभारी अर्जुन गुप्ता एवं मंडल सह प्रभारी शैलेंद्र यादव के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सदस्य तथा संचार एवं संकर्म समिति के सभापति विनोद कुमार यादव ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर समर्थन व्यक्त किया और संगठन की नीतियों एवं आगामी कार्यक्रमों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इनकी गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुई बैठक

बैठक में जिला मीडिया प्रभारी एवं मंडल प्रभारी अर्जुन गुप्ता, जिला सह मीडिया प्रभारी एवं सह मंडल प्रभारी शैलेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य एवं संचार एवं संकर्म समिति के सभापति विनोद कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष दिनेश राठौर, मंडल महामंत्री हेमंत तिवारी, प्रताप सिंह कंवर, जिला मीडिया सह प्रभारी संजय राठौर, जिला सोशल मीडिया सहसंयोजक नीरज ठाकुर, मंडल उपाध्यक्ष बेबी सिंह तंवर, रठलाल पाटले, अशोक राजवाड़े, मणिशंकर पाटले, रविन्द्र राठौर (सचिन), रमेश यादव, देशु पटेल, प्रवीण कुर्रे, गिरजा बिझबार, मनाराम दियार, जितेंद्र राठौर, समयलाल पाटले, शिवरतन राठौर, अर्जुन लाल राठौर, गोपाल विंध्यराज, मीरा जायसवाल, राजकुंवर, शगुनबाई, नौनीबाई, सनबाई, शांति दास, अमीतदास, पप्पू राठौर, राजेन्द्र कुमार, अमीत दास, चैतु यादव, सजन कुमार, नरोत्तम राजवाड़े, लक्ष्मी नारायण, विवेक राजवाड़े, लंबोदर कश्यप, प्रेम सागर व दिलहरण विश्वकर्मा सहित मंडल पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक, बूथ अध्यक्ष तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, आगामी गतिविधियों की रूपरेखा एवं बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाकर जनता से सतत संवाद बनाए रखें : अर्जुन गुप्ता

मंडल प्रभारी अर्जुन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने प्रत्येक बूथ पर संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाने तथा जनता के बीच निरंतर संवाद एवं संपर्क बनाए रखने पर बल दिया। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं से पूर्ण समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आग्रह किया।

संगठनात्मक बैठक का सफल संचालन हेमंत तिवारी ने किया, प्रताप सिंह कंवर ने जताया आभार

कार्यक्रम के अंत में मंडल महामंत्री प्रताप सिंह कंवर ने सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जबकि बैठक का सफल संचालन मंडल महामंत्री मिलाप ने किया। उत्साहपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई इस बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा भाजपा की विचारधारा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

आंधी-तूफान से पेड़ गिरने की घटना में तीन युवकों की मौत का मामला, वन विभाग के कार्य से नहीं था कोई संबंध

जांच में पंचों ने दी जानकारी

कोरबा (दिव्य आकाश)।

पाली विकासखण्ड के ग्राम चोरकाडांड में 30 मई 2026 को हुई दुखद दुर्घटना के संबंध में प.स.राहा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर ग्रामीणों एवं पंचों से जानकारी प्राप्त की गई। जांच के दौरान पंचों ने लिखित बयान देकर घटना के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की। पंचों के अनुसार, 30 मई 2026 को लगभग अपराह्न 03 बजे अचानक तेज आंधी-तूफान आने से गांव के समीप स्थित एक बड़ा घावड़ा वृक्ष जड़ से टूटकर गिर गया। उस समय वृक्ष के नीचे बैठे तीन युवक उसकी चपेट में आ गए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान तीनों युवकों की मृत्यु हो गई। पूछताछ में पंचों ने बताया कि घटनास्थल के निकट वन प्रबंधन समिति चोरकाडांड द्वारा सुअर पालन हेतु शेड निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, किंतु मृतक युवक उक्त निर्माण कार्य में संलग्न नहीं थे। घटना के समय वे वृक्ष के नीचे बैठे थे। पंचों ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि मृतकों का वन विभाग अथवा शेड निर्माण कार्य से कोई संबंध नहीं था तथा यह दुर्घटना प्राकृतिक कारणों से आई आंधी-तूफान के दौरान वृक्ष गिरने के कारण हुई।

सुखरीकला, तानाखार, चिर्रा और खैरभवना में जनसमस्या निवारण शिविर आज

कोरबा (दिव्य आकाश)।

सुशासन तिहार 2026 के तहत ग्रामीणों के समस्याओं, मांग एवं शिकायतों के निराकरण और उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने व लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से 05 जून को प्रातः 10 बजे से विकासखंड करतला के कलस्टर ग्राम सुखरीकला, पोंड़ी-उपरोड़ा के ग्राम तानाखार, कोरबा के ग्राम चिर्रा और कटघोरा विकासखंड के ग्राम खैरभवना में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित की जायेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विभागीय अधिकारियों को शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं। साथ ही ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई है।

SECL कुसमुंडा खदान के कोल स्टॉक में आग: लाखों टन कोयला जलने की आशंका, मीथेन गैस और भीषण गर्मी को माना जा रहा कारण

कोरबा/कुसमुण्डा (दिव्य आकाश)।

SECL कुसमुंडा क्षेत्र की 29 नंबर कोयला स्टॉक यार्ड में गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कोयले के विशाल ढेर से उठती लपटें और काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देता रहा। घटना से लाखों टन कोयले के जलने और करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, SECL प्रबंधन द्वारा मानसून से पहले बड़े पैमाने पर कोयले का भंडारण किया जा रहा था। इसी क्रम में 29 नंबर स्टॉक यार्ड में लाखों टन कोयला डंप किया गया था। बुधवार दोपहर अचानक कोयले के ढेर से धुआं निकलना शुरू हुआ, जो कुछ ही समय में भीषण आग में बदल गया।

शुरुआती तौर पर भीषण गर्मी और कोयले में मौजूद मीथेन गैस को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। खदान क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ने

के कारण कोयले के स्टॉक में स्वतः दहन (स्पॉन्टेनियस कंबशन) की घटनाएं बढ़ रही हैं। कर्मचारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से खदान क्षेत्र में लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी कोयला स्टॉक में धुआं या आग की स्थिति बन रही है।

आग लगने की सूचना मिलते ही SECL के दमकल वाहन और पानी के टैंकर मौके पर पहुंच गए। कर्मचारियों और अधिकारियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास शुरू किए, लेकिन समाचार लिखे जाने तक आग की धधक बढ़ती जा रही है।

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित

कोरबा (दिव्य आकाश)।

एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा (शहरी) अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका के 02 रिक्त पदों के लिए 05 जून 2026 से 19 जून 2026 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन करने हेतु नवीन पोर्टल httpsÑ//aww.e.bharti.in में पंजीयन कर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र पर पद एवं केन्द्र के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा। वार्डवार सहायिकाओं के रिक्त पदों की जानकारी कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा (शहरी) से प्राप्त की जा सकती है। इस पद हेतु आवेदिकाओं को उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है। आवेदिकाओं की आयु 18 से 44 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीण होना चाहिए। इच्छुक आवेदिकाएं ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन के प्रिंट आउट सहित आवश्यक दस्तावेजों को संर्लन कर निर्धारित समय सीमा में अपना आवेदन सीधे अथवा साधारण/पंजीकृत डाक से कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना कोरबा (शहरी) में प्रातः 10 बजे से 05 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में जमा कर सकते हैं। आवेदन की शर्तें तथा प्रारूप परियोजना कार्यालय कोरबा (शहरी), नगर पालिक निगम कोरबा के एवं संबंधित वार्डों के आंगनबाड़ी केन्द्रों के सूचना पटल पर उपलब्ध है। नियुक्ति के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

सायकल रैली 07 जून को

कोरबा। संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण रायपुर के निर्देशानुसार विश्व सायकल दिवस के उपलक्ष्य में 07 जून रविवार को सायकल रैली का आयोजन कोरबा जिला के एस.ई.सी.एल व्हॉलीबॉल मैदान से प्रातः 07 बजे प्रारंभ होकर घण्टाघर चौक से पुनः वापस एस.ई.सी.एल व्हॉलीबॉल मैदान में समापन किया जायेगा। कार्यक्रम को सफल बनाने सभी की उपस्थिति के लिए आग्रह किया गया है।

दिव्य आकाश

कोरबा से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रथम बहुरंगी साप्ताहिक अखबार

अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी, विक्रम संवत् 2083, कोरबा, शुक्रवार, दिनांक 05 से 11 जून 2026

विश्व धरा का श्रृंगार करें हम, आओ डगर-डगर पेड़ लगाएं हम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते हैं कि हम सबके जीवन में माँ का दर्जा सबसे ऊपर है। माँ हर दुःख सहकर बच्चों का लालन-पालन करती है। जन्मदात्री माँ का यह प्यार हम सब पर एक कर्ज होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। माँ के नाम एक-एक पेड़ लगाएं और माँ भारती को हरा-भरा कर कर्ज लौटाने का फर्ज निभाएं।

विश्व पर्यावरण दिवस
05 जून 2025

तभी आएगी हरियाली,
जब पेड़ों की होगी रखवाली।

छत्तीसगढ़ महतारी के मान बढ़ावव
अचरा म जगह-जगह पेड़ लगावव

जीवन का ये हैं आधार
पर्यावरण सुरक्षा करो अपार।

प्रदेश भर में 3.85 करोड़ पौधों का रोपण, पर्यावरण दिवस 05 जून 2025 से होगा प्रारंभ

छत्तीसगढ़ में वन विभाग द्वारा हरियर छत्तीसगढ़ एवं नदी तट वृक्षारोपण योजना के तहत प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान हरियाली प्रसार एवं वन संवर्धन के लिए वृहद स्तर पर 2 करोड़ 50 लाख पौधे के रोपण एवं वितरण का कार्य किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। पौधरोपण अंतर्गत आम, जामुन, बेल, कटहल, मुनगा, सीताफल, पपीता, अनार, नींबू, शहतूत, बादाम, बेर, तेन्दू, गंगा ईमली, लीची, आदि प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी प्रदेश में हरियाली लाने के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम लगाने पीएम की अपील के बाद से पौध रोपण एक योजना नहीं बल्कि अभियान के तहत पूरे देश में पौधरोपण का काम चल रहा है।

निशांत कुमार (आईएफएस)
वनमण्डलाधिकारी-वनमण्डल कटघोरा
संजय त्रिपाठी - उपवनमण्डलाधिकारी कटघोरा
चंद्रकांत टिकरिहा - उपवनमण्डलाधिकारी पाली

सांसे हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम।

सुखमय होगा तभी जीवन
जब समृद्ध होगा पर्यावरन।

शुभम मिश्रा
वन परिक्षेत्राधिकारी कटघोरा
वन मण्डल कटघोरा

पेड़ पौधों में रहते भगवान
वन रक्षा में करो योगदान।

अभिषेक दुबे
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र केंदई
वनमण्डल कटघोरा

प्रकृति का न करें हरण,
आओ बचाएं पर्यावरण।

वन है तो जल है -
जल है तो कल है।

गजेन्द्र दोहरे
वन परिक्षेत्राधिकारी जटगा
वनमण्डल कटघोरा

पर्यावरण दिवस रोज मनाएं
धरती को रहने योग्य बनाएं।

वन परिक्षेत्राधिकारी पसान
वनमण्डल कटघोरा

वनों की रक्षा में करें योगदान
तभी बनेगा देश -प्रदेश महान।

वायपीएस बंजारे
वन परिक्षेत्राधिकारी पाली
वनमण्डल कटघोरा

स्वच्छ पर्यावरण से नाता जोड़ो,
बीमारियों से मुंह मोड़ो।

दिनेश कुर्रे
वन परिक्षेत्राधिकारी चैतमा
वनमण्डल कटघोरा

सरोकार

आओ पेड़ लगाएं हम

आज पूरा विश्व इस बात को लेकर चिंतन कर रहा है कि हमसे जो गलतियां हुई हैं, उनका सुधार करना आवश्यक है। अंधाधुंध पर्यावरण की क्षति, खनिज संपदाओं का अंधाधूंध दोहन और प्रकृति के साथ अंधाधूंध छेड़छाड़ कर हमने अपने भविष्य के साथ ही छेड़छाड़ कर लिया। आज पर्यावरण संकट सर से ऊपर पानी चला गया, की कहावत चरितार्थ हो रही है और इस विकट समस्या का समाधान का मात्र एक ही विकल्प है और वह है अधिक से अधिक पेड़ एवं पौधरोपण। औद्योगिक क्रांति ने हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसा प्रेरित किया कि हम समानांतर विकास की जगह एक तरफा विकास किया और प्रकृति का विनाश करते हुए हम औद्योगिक विकास को बल दिया। हमें आधुनिक संसाधन उपलब्ध तो हुए, लेकिन यह हमें भारी महंगा पड़ रहा है। एक तरफ औद्योगिक विकास के कारण हमारा रहन-सहन का स्तर ऊंचा हुआ, लेकिन हमारा असली धन नष्ट होने लगा। स्वास्थ्य धन को सबसे बहुमूल्य धन माना जाता है, जिसमें हम पिछड़ते गए। हमें कभी-कभी लगता है कि सांस लेने में घूटन सी महसूस होती है, इसका एकमात्र कारण पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी होना, जो जीवन के लिए अतिमहत्वपूर्ण कारक है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और जब पर्यावरण बचेगा, तभी हम बचेंगे। पौध रोपण बेहतर जीवन का आधार है और इसमें एक-एक व्यक्ति की सहभागिता अतिआवश्यक है।

-संपादक

59 की उम्र में भी माधुरी की जवानी झलकती है

पर्यावरण हमारे जीवन का वह व्यापक तंत्र है जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, नदियां, जैव विविधता और जलवायु सब शामिल हैं। इसी तंत्र पर हमारी खेती, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और भविष्य निर्भर करता है। इसी साझा जिम्मेदारी और चिंता को केंद्र में रखने के लिए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।

चेतावनी: पृथ्वी बहस नहीं करती, सिर्फ संकेत देती है!

विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून पर विशेष

जीवन को शास्वत बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण को हमें अपनी जीवन शैली में एक आदत के रूप में शामिल करना होगा। सिर्फ मानव जीवन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्माण्ड का जीवन इसी पर निर्भर है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जाए और उबल रही धरती तथा आसमान के संतुलन को कैसे बनाए रखें। धरती बहस नहीं करती, सिर्फ संकेत देती है... कि अभी से सुधर जाओ, नहीं तो मुझे छेड़ोगे तो दुष्परिणाम तुम्हें ही भोगना पड़ेगा।

बेमौसम बारिश, समय से अधिक गर्मी और बारिश के मौसम में तुफानी तबाही, यह सब हमारी गलतियों का दुष्परिणाम ही है। हमने विकसित राष्ट्र के लिए औद्योगिक क्रांति को इतना बढ़ावा दिया कि पर्यावरण की जो क्षति हुई, उसकी भरपाई शायद ही कर पाएं। 1973 में ही विश्व इस भयावह संकट से रूबरू होने लगा और विश्व ने इस संकट से निपटने के लिए एक विश्व स्तरीय मंच बनाने का फैसला किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगवाई में 05 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला किया और 05 जून 1974 से पूरे विश्व ने इस तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के साथ वैश्विक मंच पर साझा कार्यक्रम तय किया कि हम प्रकृति संरक्षण को अपनी जीवनशैली में शामिल करेंगे और आह्वान किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति संरक्षण को अपनी आदत बनाएंगे। आज हम चिंतन तो करते हैं, लेकिन अपनी आदत में प्रकृति को तवज्जो नहीं देते, जिसके कारण ही 1973 से आज तक प्रकृति संरक्षण में अभूतपूर्व सफलता नहीं मिल पाई।

प्रकृति संरक्षण के साथ प्रदूषण मुक्त विश्व बनाने की बड़ी चुनौति आज भी मुंहबांय खड़ी हुई है। भारत ने भी इस बड़ी चुनौति को स्वीकार किया और राष्ट्रीय स्तर पर कई योजनाएं बनाई और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम योजना निकालकर भारतवासियों से अपील की कि प्रत्येक व्यक्ति मानसून में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल हों और इस योजना को महाअभियान के साथ महाआंदोलन का रूप दें।

धरती को जहर से बचाना होगा – संपादक की कलम से

आज धरती का एक-एक कोना जहरीला हो चुका है और आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार नहीं रूकी, तो मानव जीवन बीमार और असहाय हो जाएगा। मानव जीवन ही नहीं, बल्कि जीव मात्र बीमार हो जाएगा।

जब तक हम रसायनिक खाद का उपयोग कम नहीं करेंगे, तो पर्यावरण संरक्षण बेमानी होगी। आज हम अधिक अन्न एवं खाद्यान्न उत्पादन के चक्कर में रासायनिक खादों का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी जहर खा कर यूं ही मरीज बन जाएगा, इसलिए धरती को जहर से बचाएं और अधिक से अधिक हर किसानों के घर में पशुधन की वृद्धि हो और जैविक खाद, रासायनिक खाद का पूर्ण विकल्प बन जाए। गांव में सांझ की बेला का वही पुराना दृश्य नजर आए, जब चरवाहा गाय-बैलों को हांकते हुए गांव की गलियां गोधूली हो जाए। सीसी रोड का उपयोग इतना ही हो, कि लोगों का आवागमन सुविधाजनक बन सके और विकास न रूके। अनावश्यक जगहों पर सीसी रोड का निर्माण बंद हो, अनावश्यक बोरवेल की खुदाई प्रतिबंधित हो और नल-जल योजना का शतप्रतिशत क्रियान्वयन हो और सभी को शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

वन संरक्षण और जैविकी के नाम से आज अरबों-खरबों रूपए हर साल सरकारी फंड से खर्च हो रहा है, लेकिन जिस तरह से धरती को हरित बनाने की योजना चलाई जा रही है, उसके हिसाब से धरती में न तो हरियाली आ रही है और न ही जैवविधता में सकारात्मक परिणाम दिख रहा है। इस बात का आंकलन भी होना चाहिए कि नौकरशाह माँ भारती के प्रति कितने निष्ठावान हैं।

भारत को रेगिस्तान बनने न दें

जंगलों की सरकारी कटाई और अवैध कटाई के कारण हमारी आबाद जमीन रेगिस्तान बनती जा रही है। नदियों की तेज रफ्तार के कारण मिट्टी का जिस वेग से क्षरण हो रहा है, उसे भी रोकना होगा। प्लास्टिक आज पर्यावरण प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इस प्रदूषण को जड़-मूल से जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का सपना... सपना ही रह जाएगा।

व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण खत्म करने का प्रयास करना होगा, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में खुलकर सांस ले सकें। हमें प्रण करना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और माँ भारती को प्लास्टिक मुक्त बनाने का हम उपहार देंगे।

आज हमारी गलतियों के कारण आबाद जमीन रेगिस्तान बनती जा रही है, नदियों में मिट्टी का कटाव रोक पाने में हम पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं और जो छोटी नदियां थीं, वह आज हमारी योजनाओं की विफलता के कारण विशाल और विकराल होती जा रही हैं, जिसके कारण नदियों के किनारे वाली आबाद जमीन भी रेत में तब्दिल होती जा रही है, जो भविष्य के लिए बड़ा संकट का संकेत है।

पृथ्वी न बोलती है, न बहस करती है, सिर्फ संकेत देती है... कि मुझे रेगिस्तान होने से बचाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए रहने के लिए एक इंच जमीन भी नहीं बचेगी। समुद्र का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे आए दिन समुद्री तूफान से तबाही आ रही और हर वर्ष विश्व के लाखों लोग इस तबाही में खामोश हो जाते हैं। जल का दायरा जिस तेजी से विश्व में बढ़ रहा है और मैदानी इलाका सिकुड़ रहा है, उससे मानव जीवन ही नहीं वन एवं वन्य जीवों को भी बड़ा खतरा है।

अधिक से अधिक पेड़ लगाना ही कई समस्याओं का समाधान है, इसलिए सरकार को भी इस बात पर गौर करना होगा, कि कोयला खदानों को खुली नहीं बल्कि अंडरग्राउंड खदानों के रूप में खोलनी चाहिए, ताकि मैदान में बसे जंगल न उजड़ पाएं। सरकारी योजनाओं के लिए अधिग्रहित वनभूमि को नष्ट किया जाता है और वादे भी होते हैं कि जितने पेड़ कटेंगे, उससे दोगुना पेड़ लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं और प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, लेकिन जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यदि हम एनएच का ही अवलोकन करें, तो देश में कई अरब पेड़ों को इस योजना ने निगल लिया और हम वाहवाही लूटने लगते हैं कि हमने इतने हजार किलोमीटर का एनएच बनाया और जनता को सुगम आवागमन की सुविधा दी, लेकिन इस सच्चाई के बीच एक काली तस्वीर भी हमें दिखाई देती है, कि जहां पेड़ से आबाद था, वह अब 100 की स्पीड से चलती गाड़ियां ही दिखती हैं और हरियाली की जगह धधकती सीमेंट कांक्रीट का एनएच।

सनातन काल में बिना पंखा-कूलर के भी महल ठंडा रहता था, क्योंकि महल के चारों तरफ हरियाली रहती थी, गांव-गांव 20 से 25 तालाब, कुंआ, बावली, जलाशय, झरने हुआ करते थे, लेकिन आज गांव-गांव कुंआ और तालाब पटते जा रहे हैं और चारों तरफ भौतिक सुविधाओं के लिए सीसी रोड, बोरवेल स्थापित किए जा रहे हैं। घर-घर बोरवेल धरती की एक-एक सांसें खींच रहा है और धरती माँ प्यास से कलबला रही है। पानी ऊपर तो आ रहा है, लेकिन हमारी सरकार ने और न ही हमने पानी को पाताल में भेजने का कोई रास्ता अपनाया। जब जलस्तर संकटग्रस्त स्तर पर नीचे जाने लगा, तब हमें बारिश के पानी का संचयन की याद आई और बड़े स्तर पर रैनवाटर हार्वेस्टिंग बनाने का फैसला किया। आज भी सरकारी ईमारतों में पर्याप्त संख्या में रैनवाटर हार्वेस्टिंग दिखता ही नहीं और सिर्फ कागजों में सिमटती इस योजना से आने वाला कल काफी खतरनाक साबित हो सकता है। आज छत्तीसगढ़ सरकार भी रैनवाटर हार्वेस्टिंग को सभी सरकारी और निजी ईमारतों में अनिवार्य कर दिया है। हमें स्वेच्छा से इसे प्राथमिकता से अपनाना होगा, तभी हमारा भविष्य कुछ बेहतर बन सकेगा।

जब देश और विश्व का एक-एक नागरिक सुधरेगा तो जलवायु में स्वच्छ परिवर्तन भी दिखाई देगा और एक पेड़ माँ के नाम अभियान को आंदोलन का रूप देना होगा। हमारी कोशिशें जब पर्याप्त होंगी, तो परिवर्तन भी पर्याप्त दिखेगा और हम तब गर्व से कह सकेंगे कि हमने नई पीढ़ी के लिए स्वच्छ और सुंदर पर्यावरण छोड़ कर जा रहे हैं। विकसित भारत का सपना देखना हमारे लिए गर्व का विषय हो सकता है और जब भारत 2047 में विकसित होगा, तब विकसित भारत के साथ हरित भारत का रूपांतरण दिखेगा तो हमें दोगुना नहीं, चार गुना गर्व होगा।

हम उस दिन गर्व करेंगे, जब शहर के घरों पर फिर गौरय्या चहकेगी, विलुप्त होते जीव फिर से जंगल के रौनक बनेंगे। एनएच के किनारे-किनारे धूप से राहत के लिए हरियाली दिखेगी, सीसी रोड के अगल-बगल में पाताल में पानी जाने के लिए उपाय किए जाएंगे। जब वातावरण में प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी नहीं दिखेगा। गांव-गांव जलाशय, तालाब, कुंए दिखेंगे और हमें हर जगह 10 फीट पर पानी उपलब्ध होगा। जंगल कटने से वीरान धरती फिर हरियाली से आच्छादित होगी। जब हमारी दैनिक दिनचर्या में प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन प्राथमिकता में होगा तो वह दिन दूर नहीं, जब माँ भारती की आंचल में स्वच्छ, सुंदर और हरित पर्यावरण दिखेगा।

निधन के बाद धर्मपत्नी बनी प्रेरणा:निशुल्क बालिका शिक्षा को लेकर आदिवासी क्षेत्रों में निदेशक डॉ. गजेंद्र तिवारी से खास बातचीत

कोरबा जिले में कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं, जो असंभव को भी संभव करने की जिद्द रखते हैं और क्षमता से अधिक कर दिखाते हैं। ऐसे लोग समाज का आईना होते हैं और समाज को नई दिशा देने के लिए प्रेरित ही नहीं करते, खुद प्रेरणा बन जाते हैं। कोरबा जिले के पाली ब्लाक मुख्यालय में स्थित छत्तीसगढ़ पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल के निदेशक डॉ. गजेन्द्र तिवारी एक विद्वत व्यक्तित्व हैं और अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर रहे हैं और कम फीस में क्षेत्र के बच्चों को उत्कृष्ठ शिक्षा छत्तीसगढ़ पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल के माध्यम से दे रहे हैं।

डॉ. गजेन्द्र तिवारी अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना तिवारी और पुत्र सौर्य सहित भरापूरा परिवार के साथ सादगी से जीवन यापन करते हुए शिक्षा और समाजसेवा को अपना ध्येय बनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगे हुए थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है और एक सामान्य जीवन असामान्य हो जाता है। डॉ. गजेन्द्र तिवारी के खुशहाल जीवन में एक ऐसा आघात लगा, कि वे टूट से गए। 21 अप्रैल 2021 को डॉ. गजेन्द्र तिवारी के लिए काला दिन साबित हुआ। 21 अप्रैल 2021 से पूर्व मार्निंगवाक के लिए अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना के साथ निकले थे, कि सड़क किनारे चल रहीं श्रीमती कल्पना तिवारी को एक वाहन ने ठोकर मारकर आगे बढ़ गया। श्रीमती तिवारी का ईलाज हुआ और वह स्वस्थ भी हो गई, लेकिन 21 अप्रैल को घर में काम करते-करते सीने में दर्द हुआ और कुछ ही मिनटों में हृदयाघात से उनका निधन हो गया।

श्रीमती कल्पना तिवारी के बिना डॉ. गजेन्द्र तिवारी अधूरे से हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारा और अपनी धर्मपत्नी की प्रेरणा को ही सम्बल बना लिया। स्व. श्रीमती कल्पना तिवारी की प्रेरणा से वे अपने विद्यालय में नि:शुल्क कन्या शिक्षा योजना की शुरूआत की और आज 05 साल से संसाधन के अभाव में भी बालिका नि:शुल्क शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉ. गजेन्द्र तिवारी की इस पहल से पाली ब्लाक की निर्धन बालिकाएं बेहतर शिक्षा ग्रहण कर आगे अपने जीवन को स्वर्णीम बनाने में लगी हुई हैं। नि:शुल्क बालिका शिक्षा योजना अनवरत रखने वाले डॉ. गजेन्द्र तिवारी से खास बातचीत के कुछ अंश-

प्रश्न 1. आदिवासी क्षेत्रों में निशुल्क बालिका शिक्षा शुरू करने का विचार आपको कैसे आया?

उत्तर: आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि अनेक प्रतिभाशाली बालिकाएँ आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यह स्थिति मेरे लिए चिंताजनक थी। तभी यह संकल्प लिया कि बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए निशुल्क बालिका शिक्षा अभियान चलाया जाए।

प्रश्न 2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर: हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बालिका केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। हम उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आत्मविश्वास और बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करना चाहते हैं।

प्रश्न 3. आदिवासी क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

उत्तर: आर्थिक कमजोरी, जागरूकता की कमी, विद्यालयों की दूरी, सामाजिक रूढ़ियाँ तथा प्रारंभिक अवस्था में पढ़ाई छोड़ देना प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

प्रश्न 4. आपके विद्यालय में कितनी बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जा रहा है?

उत्तर: हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष चयनित बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है। हम इस संख्या को निरंतर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बेटियाँ लाभान्वित हो सकें।

प्रश्न 5. क्या इस योजना में केवल शुल्क माफी है या अन्य सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं?

उत्तर: शुल्क माफी के साथ-साथ शैक्षणिक मार्गदर्शन, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सहभागिता और व्यक्तित्व विकास के अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रश्न 6. ग्रामीण और आदिवासी परिवारों की इस पहल के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है?

उत्तर: परिवारों ने इस पहल का स्वागत किया है। अब अभिभावक अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के प्रति अधिक उत्साहित और जागरूक दिखाई देते हैं।

प्रश्न 7. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए?

उत्तर: समाज को बेटा-बेटी में भेदभाव समाप्त कर शिक्षा को समान अवसर के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सामाजिक सहयोग से ही शिक्षा का वास्तविक विस्तार संभव है।

प्रश्न 8. क्या आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में कमी आई है?

उत्तर: हाँ, हमारी पहल के बाद कई बालिकाएँ पुन: शिक्षा से जुड़ी हैं और विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति में सकारात्मक कमी देखने को मिली है।

प्रश्न 9. आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं?

उत्तर: हम छात्रवृत्ति, कैरियर मार्गदर्शन, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

प्रश्न 10. सरकार और निजी शिक्षण संस्थानों को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए?

उत्तर: अधिक छात्रवृत्तियाँ, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ, जागरूकता अभियान तथा बालिका शिक्षा के लिए विशेष सहयोगात्मक योजनाएँ संचालित की जानी चाहिए।

प्रश्न 11. कोई ऐसी सफलता की कहानी बताइए जिसने आपको प्रेरित किया हो।

उत्तर: कई बालिकाएँ जो कभी आर्थिक कठिनाइयों के कारण पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में थीं, आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उनकी सफलता हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।

प्रश्न 12. शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालिकाओं के जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं?

उत्तर: उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हुई है और वे अपने परिवार तथा समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

प्रश्न 13. आप बालिका शिक्षा को समाज के विकास से किस प्रकार जोड़ते हैं?

उत्तर: एक शिक्षित बालिका केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती, बल्कि वह पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित और जागरूक बनाती है।

प्रश्न 14. जो अभिभावक आज भी बेटियों की शिक्षा को महत्व नहीं देते, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर: बेटी को शिक्षा देना सबसे बड़ा निवेश है। शिक्षित बेटी परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास की मजबूत आधारशिला बनती है।

प्रश्न 15. आपकी दृष्टि में शिक्षित बालिका आदिवासी समाज के भविष्य को कैसे बदल सकती है?

उत्तर: शिक्षित बालिका सामाजिक जागरूकता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और नेतृत्व क्षमता के माध्यम से पूरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।

प्रश्न 16. आगामी पाँच वर्षों में बालिका शिक्षा को लेकर आपका सपना क्या है?

उत्तर: मेरा सपना है कि हमारे क्षेत्र की कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित न रहे और प्रत्येक बेटी को अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर मिले।

प्रश्न 17. देश के अन्य विद्यालयों और संस्थानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

उत्तर: शिक्षा को सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखें। यदि प्रत्येक संस्था कुछ बालिकाओं की शिक्षा का दायित्व ले, तो बड़ा परिवर्तन संभव है।

प्रश्न 18. शिक्षा के क्षेत्र में आपका अगला बड़ा लक्ष्य क्या है?

उत्तर: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, डिजिटल सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा का विस्तार तथा आदिवासी अंचलों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना मेरा प्रमुख लक्ष्य है।

निदेशक का संदेश - डॉ. गजेंद्र तिवारी

'जब एक बेटी शिक्षित होती है, तब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा परिवार, समाज और राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हमारी कोशिश है कि शिक्षा का प्रकाश अंतिम पंक्ति में खड़ी बालिका तक पहुँचे।'

वन भूमि की सुरक्षा के लिए बलौदाबाजार वनमंडल में विशेष अभियान शुरू

15 जून तक चलेगा एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, वन क्षेत्रों की होगी सघन निगरानी

बलौदाबाजार (दिव्य आकाश)।

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार वनमंडल में 1 जून से 15 जून 2026 तक विशेष एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया गया है। वर्षा ऋतु से पहले वन भूमि पर संभावित अतिक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से वनमंडल स्तर पर अंतर-परिक्षेत्रीय संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। ये दल विभिन्न वन क्षेत्रों का भ्रमण कर वन भूमि की स्थिति का आकलन करेंगे और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

अभियान के तहत वन सीमाओं, वनखंडों और बीट क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा जिनकी सीमाएं गांवों और कृषि भूमि से लगी हुई हैं। निरीक्षण के दौरान वन सीमांकन, मुनारों की स्थिति, संभावित अतिक्रमण, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन तथा अन्य अनधिकृत गतिविधियों की जांच की जाएगी।

निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए बने संयुक्त निरीक्षण दल

अभियान को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न वन परिक्षेत्रों के अधिकारियों को अन्य परिक्षेत्रों में निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित अभिलेख, नक्शे, कक्ष इतिहास और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण भी किया जाएगा। स्थानीय वन समितियों की सहभागिता से निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।

वन क्षेत्रों में मानवीय दबाव का भी होगा आंकलन

निरीक्षण दल वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों, पशुओं के दबाव, खरपतवार की स्थिति तथा वन अधिकार मान्यता पत्रों की स्थिति और सत्यापन का भी मूल्यांकन करेंगे।

इसके साथ ही वन संरक्षण और सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सुझाव भी एकत्र किए जाएंगे। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने कहा कि वन भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के माध्यम से वन क्षेत्रों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी नए अतिक्रमण या अवैध गतिविधि के खिलाफ नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान वन संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे वन संपदा की रक्षा और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरित विरासत का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पर्यावरण पर छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय गौरव

लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को मिला पर्यावरण चौंपियन अवार्ड 2026

100 से अधिक नामांकनों में देश की चुनिंदा 9 संस्थाओं में बनाया स्थान

नारायणपुर (दिव्य आकाश)।

पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि, वृक्षारोपण, नशामुक्ति जागरूकता एवं जनसहभागिता आधारित पर्यावरणीय अभियानों में उत्कृष्ट एवं नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अधीनस्थ लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, नारायणपुर को 01 जून को देहरादून में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित 'पर्यावरण चौंपियन अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नमामि गंगे परियोजना तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया गया। देशभर से प्राप्त 100 से अधिक नामांकनों में से कठोर मूल्यांकन एवं बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया के पश्चात केवल 9 संस्थाओं को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें एक विश्वविद्यालय, पांच विद्यालय एवं तीन महाविद्यालय शामिल थे।

सम्मानित संस्थाओं में बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि शामिल थे। चयनित संस्थाओं में उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध सामुदायिक रेडियो 'रेडियो केदार' भी सम्मिलित रहा। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी मंच पर नारायणपुर महाविद्यालय का चयन संस्था के उत्कृष्ट पर्यावरणीय कार्यों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। समारोह के दौरान सभी चयनित प्रतिभागियों एवं संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, वृक्षारोपण एवं जनजागरूकता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की वीडियो प्रस्तुति प्रदर्शित की गई। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय, नारायणपुर द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों एवं उपलब्धियों को उपस्थित विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों एवं प्रतिभागियों द्वारा विशेष सराहना प्राप्त हुई।

लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय को यह सम्मान ट्रॉफी एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर दिया गया। यह सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, प्रख्यात पर्यावरणविद्, मैती आंदोलन के प्रणेता एवं जल-जंगल-जमीन संरक्षण के राष्ट्रीय प्रेरणास्रोत, तथा विशिष्ट अतिथि पद्मश्री श्रीमती मधुरी बर्थवाल, सुप्रसिद्ध लोकगायिका, लोकसंस्कृति संवाहक एवं उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की सशक्त प्रतिनिधि के करकमलों से प्रदान किया गया। कार्यक्रम में डॉ. रुचि बडोला, डीन, फैकल्टी ऑफ वाइल्डलाइफ साइंसेज एवं नोडल अधिकारी परियोजना की गरिमामयी उपस्थिति रही।

उल्लेखनीय है कि लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, नारायणपुर द्वारा विगत वर्षों में जैविक खेती को बढ़ावा देने, व्यापक वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण गतिविधियों, नशामुक्ति जनजागरूकता कार्यक्रमों, किसानों एवं विद्यार्थियों के प्रशिक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। इन्हीं सतत, प्रभावशाली एवं समाजोपयोगी प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देते हुए संस्थान को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। यह उपलब्धि केवल महाविद्यालय की नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिवार, बस्तर संभाग एवं संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त यह सम्मान इस बात का प्रमाण है कि दूरस्थ अंचलों में भी समर्पण, नवाचार और जनसहभागिता के माध्यम से किए गए कार्य देशभर के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। 'जब शिक्षा, समाज और प्रकृति संरक्षण का संकल्प एक साथ आगे बढ़ता है, तब परिवर्तन की नई इबारत लिखी जाती है। 'पर्यावरण चौंपियन अवार्ड 2026' नारायणपुर की धरती से उठी उसी सकारात्मक पहल को मिला राष्ट्रीय सम्मान है।

05 जून पर्यावरण दिवस

छत्तीसगढ़ पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल छत्तीसगढ़ पर्यावरण रत्न सम्मान से होगी सम्मानित

बिलासपुर/पाली (दिव्य आकाश)।

पर्यावरण एवं पर्यटन विकास समिति बिलासपुर, छत्तीसगढ़ी राजभाषा परिषद, वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में 05 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस पर सरस्वती शिशु मंदिर सभागार तिलक भवन बिलासपुर में पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन विषय पर प्रतियोगिताएं, कार्यशाला, काव्य गोष्ठी, नृत्य, गीत-संगीत, फैंसी ड्रेस, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता सहित पर्यावरण क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली प्रतिभाओं एवं संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में यह समारोह सम्पन्न होगा, जिसकी अध्यक्षता विनय पाठक करेंगे। इनके अलावा कई शिक्षाविद, पर्यावरणविद कार्यक्रम का गौरव बढ़ाएंगे। आईएफएस एस एस डी बड़गैया, समाजसेवी शैलेन्द्र सिंह कछवाहा, वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु कुमार तिवारी, आईएफएस नीरज जी, डॉ. अभिलाषा बेहार, आईएसएस रमेशचंद्र श्रीवास्तव, समाजसेवी राजीव नयन शर्मा, क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिकारी श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, पर्यावरणविद हेमंत कुमार गौर सहित अन्य विभूतियां उपस्थित रहेंगी।

इस सम्मान समारोह में पाली स्थित छत्तीसगढ़ पब्लिक हायर सेकेण्डरी स्कूल को भी छत्तीसगढ़ पर्यावरण रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय के डायरेक्टर डॉ. गजेन्द्र तिवारी ने बताया कि विद्यालय परिसर को स्वच्छ, सुंदर एवं हरितिमा बनाने के साथ-साथ जल संरक्षण और वर्षा जलसंचयन, प्लास्टिक मुक्त अभियान एवं बच्चों द्वारा पर्यावरण जागरूकता रैलियों के माध्यम से समाज को पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश देना एवं पौध रोपण जैसे विविध कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

डॉ. गजेन्द्र तिवारी ने बताया कि यह विद्यालय के लिए गौरव की बात है और एक बड़ी उपलब्धि भी।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पहले चरण में 12 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में पहुंचे 12 करोड़ रुपये

मानसून से ठीक पहले भुगतान होने से वनाश्रित परिवारों को खरीफ फसल की तैयारियों में मिलेगी मदद

बीजापुर (दिव्य आकाश)।

छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए संग्रहण पारिश्रमिक (मजदूरी) दर में भारी बढ़ोतरी की है। इसके तहत अब संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, चरणपादुका योजना फिर से शुरू करके संग्राहकों को सुरक्षा और आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण सीजन 2026 के तहत छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों को आर्थिक संबल मिलना शुरू हो गया है। राज्य शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक भुगतान की प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ कर दी गई है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के अंतर्गत प्रथम चरण में 12 हजार 379 संग्राहकों के बैंक खातों में 12 करोड़ रुपये की राशि सीधे ऑनलाइन (डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित की गई है।

जिले में कुल संग्राहक व मात्रा

बीजापुर जिले की 28 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 45 लॉटों में कुल 40 हजार 716 संग्राहकों ने 65 हजार 430.359 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया है। शासन द्वारा निर्धारित 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से जिले के संग्राहकों को कुल 35.99 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक भुगतान किया जाना है। इसके अलावा 500 गड्डी से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले संग्राहकों को शासन की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 4 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है।

प्रथम चरण में समिति-वार हुआ भुगतान

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार भुगतान के पहले चरण में जिले की प्रमुख समितियों के बैंक खातों में राशि सीधे (डीबीटी के माध्यम से) जमा की गई है। प्राथमिक वनोपज समिति लाभान्वित संग्राहक हस्तांतरित राशि गुडमा समिति के 1,912 संग्राहकों को 1.95 करोड़ रुपये, कुटरू समिति के 937 संग्राहकों को 1.29 करोड़ रुपये, तोयनार समिति के 961 संग्राहकों को 1.20 करोड़ रुपये तथा बरदेला समिति के 1,023 संग्राहकों को 1.11 करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा की गई है। इसके अलावा संतोषपुर, भैरमगढ़, माटवाड़ा, कोडोली, नैमेड़, भद्रकाली और चेरपल्ली सहित अन्य समितियों के संग्राहकों को भी लाखों रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। शेष समितियों में संग्रहित मात्रा का सत्यापन और ऑनलाइन एंट्री का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसके पूरा होते ही सभी पात्र संग्राहकों को भुगतान कर दिया जाएगा।

वनाश्रित परिवारों की आजीविका को संबल

वनोपज आधारित आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की यह पहल बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। तेन्दूपत्ता बिक्री से प्राप्त इस राशि का उपयोग वनाश्रित परिवार अपनी खेती-किसानी, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करते हैं। मानसून के आगमन से ठीक पहले पारिश्रमिक राशि मिलने से किसानों और वनाश्रित परिवारों को खरीफ फसल की तैयारियों के लिए खाद-बीज आदि की व्यवस्था करने में विशेष सहायता मिलेगी। शासन की इस पारदर्शी और त्वरित ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और वन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

05 विश्व पर्यावरण दिवस

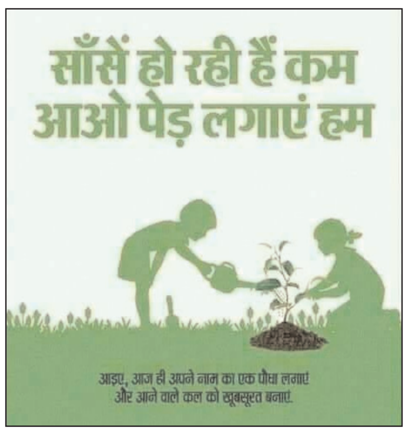

डोंगनाला का हरिबोल स्वयं सहायता समूह बना महिला सशक्तिकरण का प्रेरक मॉडल

कोरबा/पाली (दिव्य आकाश)।

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से कोरबा जिले के कटघोरा वन प्रभाग अंतर्गत डोंगनाला की आदिवासी महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। डोंगनाला का हरिबोल स्वयं सहायता समूह आज हर्बल उद्यमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का एक आदर्श बनकर उभरा है।

दिहाड़ी मजदूरी से सफल उद्यमिता तक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री केदार कश्यप की मंशानुरूप 12 आदिवासी महिलाओं से गठित इस समूह की सदस्य पहले दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर थीं। सीमित रोजगार और अस्थिर आय के कारण परिवार की जरूरतें पूरी करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन शासन की वन धन विकास केंद्र योजना से जुड़ने के बाद इन महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया।

प्रशिक्षण और तकनीकी

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध औषधीय पौधों और लघु वनोपज की संभावनाओं को देखते हुए महिलाओं को संगठित किया गया। उन्हें आयुर्वेद विशेषज्ञों तथा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा हर्बल प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन का विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

हर्बल उत्पादों की बढ़ी मांग

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समूह ने त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, हर्बल फेस पैक, हर्बल हेयर पाउडर और टूथ पाउडर जैसे गुणवत्तापूर्ण हर्बल उत्पाद तैयार करना शुरू किया। गुणवत्ता और प्रभावशीलता के कारण इन उत्पादों की स्थानीय तथा संस्थागत बाजारों में अच्छी मांग बनी।

आयुष विभाग से मिला बड़ा ऑर्डर

समूह को उस समय बड़ी सफलता मिली जब उन्हें आयुष विभाग से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ। इस ऑर्डर से समूह को लगभग 20 लाख रुपए का लाभ हुआ। इससे समूह की विश्वसनीयता बढ़ी और नए बाजारों के द्वार खुले।

38.90 लाख रूपए का लाभ

वित्तीय वर्ष 2024-25 में समूह ने लगभग 38.90 लाख रुपए का लाभ और कमीशन अर्जित किया। इससे सदस्यों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तथा जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया।

26.11 करोड़ रूपए की संचयी बिक्री

वर्ष 2020 से मार्च 2026 तक वीडीवीके डोंगनाला ने लगभग 26.11 करोड़ रूपए की संचयी बिक्री दर्ज की है। यह उपलब्धि समूह की निरंतर मेहनत, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और प्रभावी विपणन रणनीति का परिणाम है।

हर सदस्य की 1.7 लाख वार्षिक आय

इस पहल से समूह की प्रत्येक सदस्य की वार्षिक आय बढ़कर लगभग 1.7 लाख रुपए हो गई है। आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ महिलाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ी है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

हर्बल प्रसंस्करण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए समूह को ट्रायफेड तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

अन्य समूहों के लिए प्रेरणा

हरिबोल स्वयं सहायता समूह की सफलता यह साबित करती है कि शासन की योजनाओं, कौशल विकास, संस्थागत सहयोग और बाजार उपलब्धता के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। डोंगनाला की यह सफलता आज पूरे प्रदेश और देश के स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रेरणास्रोत बन गई।

मोर गांव मोर पानी अभियान

'नवा तरिया आय के जरिया' से जल संरक्षण के साथ बढ़ रहा ग्रामीण रोजगार

छत्तीसगढ़ में जल आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रभावी पहल, नए तालाबों से सिंचाई, भूजल संवर्धन और आजीविका को मिल रहा बल

बलरामपुर (दिव्य आकाश)।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से संचालित मोर गांव मोर पानी अभियान सकारात्मक परिणाम दे रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में शुरू की गई 'नवा तरिया आय के जरिया' पहल जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में जिले में नवीन तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। इन जल संरचनाओं का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को संजोना,

भूजल स्तर में सुधार लाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी जल स्रोत विकसित करना है। जिले में वर्तमान में 12 नए तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें विकासखंड बलरामपुर में 2, कुसमी में 2, राजपुर में 1, रामचंद्रपुर में 4, शंकरगढ़ में 1 तथा वाड्रफनगर में 2 तालाब शामिल हैं। इनमें से 9 स्थानों पर निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रत्येक निर्माण स्थल पर प्रतिदिन लगभग 40 से 50 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, जिससे जल संरक्षण के साथ ग्रामीण परिवारों की आय में भी वृद्धि हो रही है। तालाबों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है। जल संग्रहण क्षमता को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए इनलेट, आउटलेट और सिल्ट ट्रैप जैसी संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। इससे मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण होगा और जलधारण क्षमता बनी रहेगी।

इन नवीन जल संरचनाओं से आने वाले वर्षों में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, भूजल स्तर में सुधार तथा पशुओं के लिए वर्षभर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होने की संभावना है। जल उपलब्धता बढ़ने से किसानों को बहुफसली खेती, सब्जी उत्पादन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों को अपनाने का अवसर मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

मोर गांव मोर पानी अभियान जनभागीदारी आधारित जल संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर सामने आ रहा है। 'नवा तरिया आय के जरिया' जैसी पहलें यह साबित कर रही हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं, बल्कि ग्रामीण समृद्धि और सतत विकास का मजबूत आधार भी है।

बालको का 'ब्लैक मेज़', महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल

बालको की प्रोजेक्ट उन्नति से जुड़कर 6000 से अधिक महिलाएं लिख रही हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता और सतत आजीविका की नई कहानी

बालकोनगर (दिव्य आकाश)।

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बालकोनगर में 'ब्लैक मेज़' का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट उन्नति की महिलाओं द्वारा संचालित यह फाइन डाइनिंग कैफे महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सामुदायिक विकास का सशक्त प्रतीक है। ताज़ा पकवानों की मनमोहक खुशबू, सलीके से सजा आकर्षक वातावरण और मेहमानों का आत्मीय स्वागत करती महिलाओं का आत्मविश्वास इसकी सफलता और परिवर्तन की कहानी है।

बालको की प्रमुख महिला सशक्तिकरण पहल 'प्रोजेक्ट उन्नति' की महिलाओं द्वारा संचालित 'ब्लैक मेज़' उस यात्रा का नया अध्याय है, जिसकी शुरुआत कभी 'उन्नति चौपाल' के रूप में हुई थी। चाट-पकौड़ी और स्थानीय व्यंजन परोसने वाला एक छोटा फास्ट-फूड केंद्र आज 50 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले आधुनिक फाइन डाइनिंग कैफे में परिवर्तित हो चुका है। निजी आयोजनों और विशेष अवसरों के लिए तैयार इसका विशेष डाइनिंग स्पेस इसकी भव्यता को और बढ़ाता है।

'ब्लैक मेज़' की सबसे बड़ी पहचान हर परोसे गए भोजन के पीछे छिपी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। इसके केंद्र में हैं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वे महिलाएं, जिन्होंने कभी स्वयं को केवल गृहिणी के रूप में देखा था। प्रोजेक्ट उन्नति के माध्यम से उन्हें व्यंजन कला, आतिथ्य सेवा, ग्राहक प्रबंधन, उद्यमिता और खाद्य गुणवत्ता जैसे क्षेत्रों में सुनियोजित प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण ने न केवल उनके कौशल को निखारा, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास भी दिया। 'ब्लैक मेज़' का डाइनिंग स्पेस भी अपने आप में खास अनुभव प्रदान करता है। यहां के मेन्यू छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों, उत्तर भारतीय स्वाद, चाइनीज़ पकवानों और लोकप्रिय फास्ट-फूड का अनूठा संगम स्थानीय संस्कृति और आधुनिकता को एक साथ प्रस्तुत करता है।

...तब मुझे अपनी उपलब्धि का एहसास हुआ-भारती

समूह की एक अन्य सदस्य भारती ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बेटी ने पूछा कि अब क्या घर पर मेरे हाथ का स्वाद मिलेगा या उसे 'ब्लैक मेज़' आना पड़ेगा। उस पल मुझे अपनी उपलब्धि का एहसास हुआ। प्रोजेक्ट उन्नति ने मुझे अपनी प्रतिभा को निखारने और पहचान बनाने का ऐसा मंच दिया है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।

अभी बहुत कुछ सीखना है - निर्मला देशमुख

उन्नति समूह की सदस्य निर्मला देशमुख ने कहा कि मैंने लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। 2022 में उन्नति से जुड़ने के बाद चार वर्षों में मैंने अपने भीतर और अपनी साथी बहनों में जो बदलाव देखा है, वह अविश्वसनीय है। हमारे पास हुनर था, लेकिन बालको के सहयोग ने हमें उसे बड़े मंच पर पहचान दिलाई।

कोरबा से आए एक ग्राहक ने कहा कि ब्लैक मेज़ का वातावरण बेहद आकर्षक है। यहां भोजन और कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है।

'ब्लैक मेज़' केवल एक कैफे नहीं, बल्कि महिलाओं द्वारा संचालित सतत उद्यमिता का प्रेरक मॉडल

'ब्लैक मेज़' केवल एक कैफे नहीं, बल्कि महिलाओं द्वारा संचालित सतत उद्यमिता का प्रेरक मॉडल है, जो आजीविका सृजन के साथ आत्मविश्वास और सांस्कृतिक गौरव को नई ऊंचाइयां देता है। बालको की यह पहल उस भविष्य की ओर संकेत करती है, जहां महिलाएं विकास की सहभागी ही नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाली नेतृत्वकर्ता बनकर उभर रही हैं।

आत्मनिर्भरता की कहानी गढ़ रहीं 6000 महिलाएं

वर्षों से प्रोजेक्ट उन्नति ने 560 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाते हुए आर्थिक आत्मनिर्भरता और सतत आजीविका के अवसर विकसित किए हैं। आज इन समूहों से जुड़ी 6,000 से अधिक महिलाएं, उन्नति महासंघ (यूएमएस) के माध्यम से संचालित विभिन्न सूक्ष्म और लघु उद्यमों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

ब्लैक मेज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने प्रेरित करेगा-सीईओ आर के सिंह

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 'बालको समुदाय, विशेषकर महिलाओं के लिए ऐसे अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उनकी आजीविका क्षमता और सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों की 6,000 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भरता और अपने परिवारों के दीर्घकालिक विकास की दिशा में आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रही हैं। मुझे विश्वास है कि 'ब्लैक मेज़' की यह पहल और अधिक महिलाओं को आगे बढ़कर अपनी सफलता की नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित करेगी।

बालको ने विभिन्न वार्डों में सुनिश्चित की पेयजल आपूर्ति

बालकोनगर (दिव्य आकाश)।

भीषण गर्मी के दौरान जल संकट से जूझ रहे समुदाय के लिए भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने वार्ड क्रमांक 40, 41 एवं 42 में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कर राहत प्रदान की। कंपनी द्वारा किए गए इस प्रयास से स्थानीय निवासियों को गर्मी के कठिन समय में बड़ी राहत मिल रही है।

वार्ड क्रमांक 42 के पार्षद सत्येंद्र दुबे ने बालको की इस पहल के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के समय बालको द्वारा विभिन्न वार्डों में जल आपूर्ति की व्यवस्था करना एक सराहनीय कार्य है। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। बालको हमेशा समुदाय की आवश्यकताओं को समझते हुए सहयोग के लिए आगे आता है, जिसके लिए मैं कंपनी का आभार व्यक्त करता हूं।

बालको की यह पहल समुदाय के प्रति कंपनी की सामाजिक प्रतिबद्धता और जनकल्याण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। नियमित जल आपूर्ति के माध्यम से अनेक परिवारों को जल समस्या से राहत मिली है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि कंपनी ने समय पर सहयोग देकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी निर्वहन किया है।

मंत्री लखन लाल ने किया बालको कूलिंग टॉवर से रिस्दा पुल तक के नाली निर्माण का शिलान्यास

बालकोनगर (दिव्य आकाश)।

मंत्री लखन लाल देवांगन ने सोमवार को शांतिनगर क्षेत्र में सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर कोरबा की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत विशेष रूप से उपस्थित रहीं। यह पहल क्षेत्रीय नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा शांतिनगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह परियोजना बालको कूलिंग टॉवर से रिस्दा पुल तक लगभग 2.9 किलोमीटर लंबाई में विकसित की जाएगी। लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 2.5 करोड़ रुपये जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) तथा 2.5 करोड़ रुपये बालको की सीएसआर निधि से प्राप्त हुए हैं। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अब निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

इस नाली निर्माण परियोजना के पूर्ण होने से शांतिनगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या का समाधान होगा। इससे क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी तथा बरसात के मौसम में होने वाली असुविधाओं से राहत प्राप्त होगी। शिलान्यास अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना स्थानीय नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और इससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।

जिला प्रशासन और बालको की साझेदारी कोरबा क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास को लगातार नई गति दे रही है। हाल ही में बजरंग चौक से रिस्दा पुल (परसाभाठा मार्ग) के उन्नयन, पुल मरम्मत और आधुनिक सड़क निर्माण की दिशा में शुरू हुई पहल के क्रम में यह नाली निर्माण परियोजना क्षेत्रीय विकास की अगली महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और आजीविका जैसे क्षेत्रों में बालको की निरंतर पहल स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास को नई गति देते हुए स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

दीर्घकालिक विकास के लिए बालको प्रतिबद्ध- राजेश कुमार सिंह

बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित यह नाली निर्माण परियोजना सामुदायिक आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, जीवन स्तर में सुधार लाने और दीर्घकालिक विकास को गति देने के प्रति बालको की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। समुदाय के साथ हमारी व्यापक सहभागिता से वित्तीय वर्ष 2026 में 1.8 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अपने समुदाय के विश्वास के लिए आभारी हैं, जिसने हमें सतत सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है।

गजानंद प्रसाद साहू के पुनः कांग्रेस ओबीसी शहर जिला अध्यक्ष बनने पर कांग्रेसजनों ने दी बधाई

जयसिंह अग्रवाल का आभार जताने कांग्रेस कार्यालय पहुंचे गजानंद प्रसाद साहू

कोरबा (दिव्य आकाश)।

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष गजानंद साहु को कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग कोरबा शहर का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश कुमार राठौर तथा विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी की अनुशंसा पर एवं कांग्रेस ओ बी सी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जयहिंद की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष केशव चंद्राकर ने जारी की है ।

गजानंद साहु को एक बार पुनः कांग्रेस ओ बी सी विभाग में जिला शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पालुराम साहु, राजेन्द्र तिवारी, ए डी जोशी, बसंत चंद्रा, मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, जवाहर निर्मलकर, सुकसागर निर्मलकर, प्रदीप जायसवाल, इकबाल कुरैशी, रोपा तिर्की, देवीदयाल सोनी, बुद्धेश्वर चौहान, सुरती कुलदीप, अश्वनी पटेल, प्रदेश सचिव विकास सिंह, बी एन सिंह, पूर्व महापौर राजकिशोर प्रसाद, पूर्व अध्यक्ष सपना चौहान, नत्थुलाल यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, सुरेन्द्र प्रताप जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहु, पार्षद बद्री किरण, अनुज जायसवाल, सुभाष राठौर, अयोध्या मस्तुल कंवर, गीता गभेल, रवि चंदेल, डॉ.रामगोपाल कुर्रे, नारायण कुर्रे, प्रेमलता अविनाश बंजारे सहित पूर्व सभापति धुरपाल सिंह कंवर, संतोष राठौर, जिला कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ठाकुर, अर्चना उपाध्याय, दुष्यंत शर्मा, अशोक लोध, आरिफ खान, महामंत्री रमेश जायसवाल, रेखा त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण देवांगन, मनीराम साहु, सुधीर जैन, एफ डी मानिकपुरी, मनहरण लाल राठौर, राजकुमार जोशी, आनंद पालीवाल, गिरधारी बरेठ, अनुराग मोहित, सचिव डॉ. एल पी साहु, रतन यादव, सुरेश पटेल, डॉ. डी आर नेताम, संजू अग्रवाल, फरियाद अली, प्रमोद श्रीवास, धनंजय चंद्रा, अनिल अग्रवाल, राजेन्द्र सूर्यवंशी, राजूधन चंदानी, संतोष यादव, कार्यकारिणी सदस्य अवधेश सिंह, शत्रुहन श्रीवास, सनीष कुमार, बिसाहु कुंभकार, सरस्वती कंवर सहित उपस्थित कांग्रेसियों ने बधाई दी।

विश्व सायकिल दिवस मनाया छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ ने

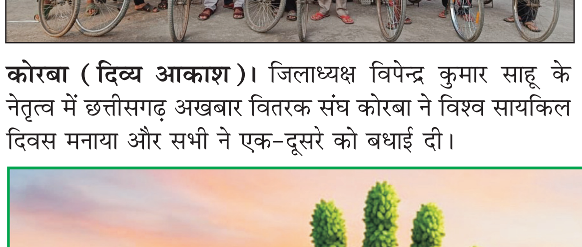

कोरबा (दिव्य आकाश)। जिलाध्यक्ष विपेन्द्र कुमार साहू के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ कोरबा ने विश्व सायकिल दिवस मनाया और सभी ने एक-दूसरे को बधाई दी।

तंत्र-मंत्र के चक्कर में 2 बेटों का मर्डर: मां समेत 4 को उम्रकैद

सक्ती। सक्ती जिले में अपने ही घर के 2 बेटों को तंत्र-मंत्र कर मर्डर करने वाले परिवार को उम्रकैद हुई है। ग्राम तांदुलडीह में 2 साल पहले यह घटना हुई थी। जहां मां और बहनें घर पर तंत्र साधना करती थीं। भाइयों ने विरोध किया तो उन्हें पानी में कीटनाशक मिलाकर पिलाया और गला घोंट दिया। मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र का है। जांच में सामने आया था कि, परिवार ने उज्जैन के उमाकांत नामक बाबा से गुरु दीक्षा ली थी। वारदात से 7 दिन पहले सभी आरोपी उपवास रखे थे। भाइयों को कमरे में बंद कर तंत्र पूजा कर रहे थे। आरोपियों में मां, 2 बहनें और एक भाई शामिल हैं, जिन्हें आजीवन कारावास हुआ है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने विविध कार्यक्रमों का होगा आयोजन

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री चौधरी होंगे मुख्य अतिथि

रायपुर (दिव्य आकाश)।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा 05 जून 2026 को होटल बेबीलॉन इंटरनेशनल, रायपुर में विविध पर्यावरणीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा युवाओं और विद्यार्थियों में प्रकृति एवं जलवायु के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 10 बजे पोस्टर प्रतियोगिता एवं इको क्लब के शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र के साथ होगा। पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों और युवाओं को पर्यावरणीय चुनौतियों तथा उनके समाधान विषयक रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाएगा।

दोपहर 3:30 बजे से पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास विषय पर संगोष्ठी तथा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी होंगे।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य सचिव राजु अगसिमनि ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को पर्यावरण संरक्षण के साझा प्रयासों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जनभागीदारी और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

पुरस्कार वितरण समारोह में पोस्टर प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर इको क्लबों की गतिविधियों, नवाचारों एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रयासों पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही प्रदेश के उत्कृष्ट इको क्लबों द्वारा संचालित पर्यावरणीय गतिविधियों एवं उपलब्धियों की विशेष प्रदर्शनी प्रस्तुत की जाएगी। कार्यक्रम में शिक्षकों, विद्यार्थियों, पर्यावरण विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी।

रायपुर में विकसित होगा विश्वस्तरीय हॉस्पिटैलिटी एवं वेलनेस सेंटर

रायपुर (दिव्य आकाश)।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा राजधानी रायपुर स्थित क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख-रखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत एजेंसी नियुक्त करने की महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह पहल रायपुर को एक आधुनिक एवं प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी तथा वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

परियोजना के तहत क्लब परिसर में स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, बिलियर्ड रूम तथा टेबल टेनिस हॉल जैसी आधुनिक खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विकसित एवं संचालित की जाएंगी। साथ ही वर्तमान अधोसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण भी किया जाएगा।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह परियोजना रायपुर को एक नए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा गुणवत्तापूर्ण शहरी अधोसंरचना विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्वींस क्लब ऑफ इंडिया की विशेष आवास योजना के अंतर्गत सांसद एवं विधायक वर्ग के 108 सदस्यों की विशेष सदस्यता पूर्ववत जारी रहेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान वर्तमान सदस्यों के हितों एवं सुविधाओं का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि परियोजना को लाइसेंस, डेवलप, ऑपरेट एवं ट्रांसफर (LDOT) मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार क्लब की मौजूदा सुविधाओं का बेहतर संचालन एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा तथा टेनिस कोर्ट क्षेत्र के रिक्त भूभाग पर लगभग 61 कमरों वाले आधुनिक आवासीय एवं हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना में लगभग 25 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास होने के साथ-साथ दीर्घकालिक राजस्व सृजन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। परियोजना की लाइसेंस अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें अतिरिक्त 10 वर्ष तक विस्तार का प्रावधान रहेगा।

श्री देव ने कहा कि शहर के प्रमुख क्षेत्रों से उत्कृष्ट सड़क संपर्क एवं बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यह परियोजना निवेशकों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसके माध्यम से राजधानी में उच्चस्तरीय आतिथ्य, खेल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र विकसित होगा।

सुशासन की उजली तस्वीर

आजादी के 78 साल बाद रोशन होंगे दूरस्थ मजराटोले, सुशासन तिहार में जिले को मिली बड़ी सौगात

खैरागढ़ (दिव्य आकाश)।

सुशासन तिहार-2026 के अवसर पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के समन्वित प्रयासों से जिले के 10 दूरस्थ एवं अब तक विद्युत सुविधा से वंचित मजराटोलों के विद्युतीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन क्षेत्रों में इसी सत्र के दौरान तेजी से विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ कर पूर्ण किया जाएगा।

आजादी के 78 वर्षों बाद जिले के ऐसे दूरस्थ वनांचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जहां अब तक अंधेरा ही ग्रामीणों की नियति बना हुआ था। मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना के तहत निजामडीह, तुम्दादाह, बलरामपुर, कोहकझोरी, संजारी-टाटीघाट, झिलमिली एवं गाताभर्री, घाघरा, लमरा, रिहाडबरा तथा टिनगीपुर जैसे गांवों के मजराटोलों में विद्युत नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

ग्रामीण विकास की नई रोशनी, शिक्षा-स्वास्थ्य और आजीविका को मिलेगा बल'

विद्युतीकरण से न केवल घरों में रोशनी पहुंचेगी, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और आजीविका के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। बिजली उपलब्ध होने से बच्चों की पढ़ाई, किसानों की सुविधाएं, छोटे व्यवसाय और शासकीय सेवाओं की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। लंबे समय से बिजली की मांग कर रहे ग्रामीणों के लिए यह निर्णय किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है।

कलेक्टर और विद्युत विभाग के प्रयासों से मिली सफलता

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे कलेक्टर इंद्रजीत चन्द्रवाल तथा विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक भीम सिंह का विशेष मार्गदर्शन और सतत प्रयास रहा है। उनके नेतृत्व में विभागीय प्रक्रियाओं को गति मिली और वर्षों से लंबित विद्युतीकरण प्रस्तावों को स्वीकृति दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।

सुशासन तिहार के दौरान मिली यह सौगात जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। आने वाले समय में इन मजराटोलों में जगमगाती रोशनी के साथ विकास की नई किरण भी पहुंचेगी, जिससे ग्रामीणों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा।

युवक की आवश्यकता है
(रिसेप्शनिष्ट)
संपर्क करें -
Snookyard Café
प्रथम मंजिल, अंकिता कॉम्पलेक्स
सुभाष चौक, निहारिका, कोरबा
मो.: 79997-72254
वेतन आकर्षक

संस्कृत विषय बचाओ अभियान: घोषणा को अमल में लाने संस्कृत शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

कोरबा (दिव्य आकाश)।

प्रदेश अध्यक्ष दौलत राम साहू के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारी नोयन कुमार बुडेक, मनोज कुमार वर्मा, डॉ नारायण प्रसाद, गंगाराम साहू, हेमंत कुमार हिरवानी, दुर्गेश कुमार साहू, कुलेश्वर प्रसाद, दिनेश मंडावी, सुनील महार, ईश्वरी यदु कामिनी पिल्लई, रेणुका लदेर, शारदा साहू, सुरेखा सेन, सोमप्रभा साहू सहित प्रदेश के पांच शिक्षा संभाग के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भारतीय संविधान में आठवीं अनुसूची की भाषा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप संस्कृत विषय के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु उल्लेख किया गया है को ध्यान में रखते हुए गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री द्वारा 30 अप्रैल को विधानसभा से घोषणा किया गया कि संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर रहे हैं, जिनका लघु चलचित्र सोशल मीडिया पर बहुत प्रसारित हैं।

इसे देख सुनकर प्रदेश भर के संस्कृत शिक्षकों में शासन की सौहार्द्रपूर्ण निर्णय से हर्ष की लहर है। संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कार परक एक राष्ट्रभाषा है, जिनमें सनातन संस्कृति पूर्ण रूप से समाहित है। संघ के पदाधिकारियों द्वारा 10 मई एवं 26 मई 2026 को नवा रायपुर स्थित एम -14 आवास में शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर घोषणा के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए शीघ्र अति शीघ्र शासकीय आदेश जारी करवाने हेतु मांग पत्र सौपा, जिससे शिक्षक आश्वस्त हो जावे तथा मंत्री द्वारा संस्कृत विषय को अनिवार्य करने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए यह शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, किन्तु आज पर्यन्त कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पदाधिकारियों ने आगे बताया कि इस पावन कार्य के लिए निरंतर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर, विधायकगण, वित्त मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री अरूण साव, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय , राज्यपाल रमेन डेका , संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, सचिव सहायक संचालक छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मण्डलम्, प्रदेश संयोजक व अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी फेड़रेशन कमल वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, डॉ अतुल कोठारी राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, आयुक्त राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा सहित 50 से भी अधिक आवेदन बारंबार संस्कृत विषय को पूर्व की भांति अनिवार्य करने तथा नवीन व्यावसायिक शिक्षा को सातवें विषय के रूप में रखने के लिए मांग पत्र ज्ञापन सौपा गया था। 25 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक में एससीईआरटी रायपुर को कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा दसवीं का संस्कृत विषय को अनिवार्य करने निर्देशित भी किया गया था। इसी क्रम में 07 सितंबर 2025 को सरयू पारिण भवन मठपुरेना में आयोजित विराट संस्कृत विद्वत सम्मेलन में उपस्थित मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह को भी मांग पत्र सौपा गया था। वहां पर अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्कृत संकल्प का विषय है विकल्प का नहीं। संस्कृत भाषा के साथ अन्याय नहीं होगा। एक तरफ पूरा विश्व संस्कृत भाषा के महत्व को अपना रहा है। अपने देश के विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में संस्कृत भाषा को अनिवार्य शिक्षा कर रहे हैं तथा अनुच्छेद 351 आठवीं अनुसूची की भाषाओं के सम्मान के लिए बनाया गया है।

साय सरकार की योजना से सम्पत्ति रजिस्ट्री कराने महिलाओं की होड़

बलौदाबाजार (दिव्य आकाश)।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों से जमीन रजिस्ट्री पर सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर महिलाओं के नाम होने वाली भूमि व संपत्ति की रजिस्ट्री (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने और 12 प्रतिशत उपकर (Cess) को पूरी तरह समाप्त करने के निर्णय से बड़ा बदलाव आया है। शासन की इस बड़ी रियायत के चलते बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने और पंजीयन कराने की होड़ सी मच गई है। आंकड़ों के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है।

एक महीने में रजिस्ट्री मामलों में 70 प्रतिशत की भारी वृद्धि

जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह छूट लागू होने के बाद मात्र एक महीने के भीतर महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्रियों में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल 2026 जिले के पांचों उप पंजीयक कार्यालयों में महिलाओं के नाम पर कुल 309 दस्तावेज पंजीकृत हुए थे। मई 2026 यह संख्या बढ़कर 445 पहुंच गई, जो अप्रैल की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाती है।

ब्लॉकवार आंकड़ों पर एक नजर (अप्रैल बनाम मई 2026)

रजिस्ट्री शुल्क में कटौती का लाभ उठाने में जिले के सभी क्षेत्र आगे रहे हैं, जिनमें शहरी इलाकों का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। उप पंजीयक कार्यालय केवल बलौदाबाजार में अप्रैल 2026 में 78 और मई 2026 में बढ़कर 119 हो गया। इसी प्रकार पलारी में अप्रैल 2026 में 40 दस्तावेज बढ़कर मई 2026 में 56, सिमगा में 56 से बढ़कर 99, कसडोल में 24से बढ़कर 50 तथा भाटापारा में 111 से बढ़कर 121 दस्तावेज हो गए। यह वृद्धि दर्शाती है कि महिलाओं को दी गई पंजीयन शुल्क छूट का लाभ बड़ी संख्या में परिवार उठा रहे हैं। शहरी क्षेत्र बलौदाबाजार और भाटपारा के आकड़ों में अधिक वृद्धि देखी गई है।

जिला पंजीयक विनोद कोचे ने बताया कि राज्य शासन की इस नीति का सीधा और त्वरित लाभ महिलाओं को मिल रहा है। संपत्ति खरीद की लागत काफी कम हो जाने से अब परिवार स्वेच्छा से महिलाओं के नाम पर जमीन और मकान पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। वहीं, बलौदाबाजार के उप पंजीयक विपुल श्रीवास्तव के अनुसार, अप्रैल 2026 से 12 प्रतिशत उपकर समाप्त होने से इस प्रक्रिया में और तेजी आई है। अकेले बलौदाबाजार कार्यालय में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक 107 अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। खास बात यह है कि इससे जहां एक तरफ आम जनता को बड़ी आर्थिक राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ रजिस्ट्री की संख्या बढ़ने से शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है।

06 से 09 जून तक होगी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

रायपुर (दिव्य आकाश)। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-2025 की लिखित परीक्षा की समय-सारिणी घोषित कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 06 जून से 09 जून 2026 तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में प्रातः 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक तथा दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक संपन्न होगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार 06 जून 2026 को भाषा एवं निबंध, 07 जून को सामान्य अध्ययन-I एवं II, 08 जून को सामान्य अध्ययन-III एवं IV तथा 09 जून को सामान्य अध्ययन-V की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 सरगुजा (अंबिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। 25 मई 2026 को अभ्यर्थियों को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

मुड़ापार में शिविर:238 आवेदनों का हुआ त्वरित निराकरण

कोरबा/पाली (दिव्य आकाश)।

सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आमजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से पाली ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुड़ापार में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती निकिता मुकेश जायसवाल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा शोभा जगत, विधायक प्रतिनिधि दुष्यंत शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को स्टॉल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी एवं विभागीय योजनाओं से लाभ प्रदान किया गया। जिसमें जनपद पंचायत पाली अंतर्गत एक हितग्राहियों को राशन कार्ड, एक हितग्राही को पेंशन स्वीकृति आदेश, 03 दिव्यांग हितग्राही को श्रवण यंत्र एवं 01 हितग्राही को वाकिंग स्टीक प्रदान किया गया। साथ ही नन्हें शिशुओं को अन्नप्राशन भी कराया गया। शिविर में विभिन्न विभाग अंतर्गत मांग व शिकायत से सम्बंधित कुल 1065 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 238 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। शेष आवेंदनों का परीक्षण कर शीघ्रता से निराकरण किया जाएगा। इस शिविर में क्लस्टर अंतर्गत शामिल सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक प्रेमचंद ने कहा कि सुशासन तिहार का मुख्य उद्देश्य शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने तथा ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारी शिविरों में उपस्थित होकर अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हैं, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन स्तर में सुधार करें।

विधायक पटेल ने कहा-सुशासन तिहार का उद्देश्य योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना

सुशासन तिहार में युवक ने मांगा हेलीकॉप्टर

बेमेतरा, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गाड़ाडीह में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक युवक ने सीधे हेलीकॉप्टर की मांग कर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने से परेशान एक ग्रामीण ने हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने की मांग कर दी। ग्रामीण राजकुमार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को दिए आवेदन में लिखा है कि ग्राम गाड़ाडीह से नवकेशा (देवकर) हाई स्कूल पहुंच मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। कई बार आवेदन देने के बावजूद सड़क निर्माण नहीं हो सका है। ऐसे में जब तक सड़क निर्माण की स्वीकृति और निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक उन्हें हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए ताकि बारिश के मौसम में कीचड़ और जलभराव से राहत मिल सके।

कांग्रेस में नियुक्तियां

गजानंद प्रसाद साहू बने पुनः कांग्रेस ओबीसी के शहर जिलाध्यक्ष

राजेश पुनः ग्रामीण जिलाध्यक्ष

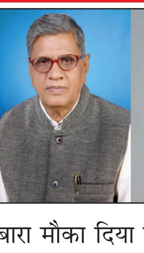

कोरबा (दिव्य आकाश)।

छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ ने कई जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। कोरबा शहर से गजानंद प्रसाद साहू को दोबारा मौका दिया गया है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष के रूप में भी राजेश मानिकपुरी को दोबारा नियुक्ति दी गई है। कांग्रेस संगठन ने बेहतर कार्य करने एवं संगठन की मजबूती के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देने वाले गजानंद प्रसाद साहू एवं राजेश मानिकपुरी को पुनः शहर एवं ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

संगठन की मजबूती के लिए प्रयास करते रहूंगा-गजानंद प्रसाद साहू

कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शहर के रूप में पुनः नियुक्ति होने के बाद नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गजानंद प्रसाद साहू ने कहा कि संगठन ने मुझे दोबारा अवसर दिया है, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। श्री साहू ने कहा कि संगठन ने जो मुझे दोबारा अवसर दिया है, उसमें मैं 100 प्रतिशत खरा उतरने का प्रयास करूंगा और संगठन की मजबूती के लिए हमेशा प्रयास टीम भावना के साथ करता रहूंगा।

कांग्रेसियों में हर्ष:दी गई बधाई

जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के शहर जिलाध्यक्ष गजानंद प्रसाद साहू एवं ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेश मानिकपुरी की नई नियुक्ति के बाद कांग्रेसियों में हर्ष है और वरिष्ठ कांग्रेसजनों सहित कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

जागरूक बनें पेड़ लगायें,
प्रदूषण को दूर भगाएं...

05 जून 2026
विश्व पर्यावरण दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं...

प्रेमलता यादव (आईएफएस)
वन मण्डलाधिकारी, कोरबा

राम सिंह राठिया
उप वनमण्डलाधिकारी, कोरबा

एस.के. सोनी
उप वनमण्डलाधिकारी, कोरबा

वन्य प्राणियों की सुरक्षा करें।

आओ करें हम वृक्षारोपण,
पर्यावरण का हो संरक्षण।

पेड़ लगाओ,
जीवन बचाओ।

जंगलों में आग न लगाएं।

प्रकृति देती है
हमें सब कुछ,
हम भी तो देना
सीखें कुछ।

जयंत सरकार
वन परिक्षेत्राधिकारी बालको
वनमण्डल कोरबा

पेड़ पौधे लगाएंगे हम,
पृथ्वी को बचायेंगे हम।

रघुनाथ सिंह गोंड़
वन परिक्षेत्राधिकारी करतला
वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

लगाओ पेड़-पौधे और दो उन्हें पानी,
पर्यावरण को दो अपनी निशानी।

घुटूर साय पैकरा
वन परिक्षेत्राधिकारी कुदमुरा
वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

बच्चों को भी दो यह शिक्षा,
पर्यावरण की करो सुरक्षा।

देवदत्त खाण्डे
वन परिक्षेत्राधिकारी पसरखेत
वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

धरती को बचाना है,
पर्यावरण रक्षा का लक्ष्य बनाना है।

देवव्रत सिन्हा
वन परिक्षेत्राधिकारी लेमरू
वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

जंगलों को आग से बचाएं।

चिड़िया चहकेगी हर डाली,
पहले फैलाओ हरियाली।

मृत्युंजय शर्मा
वनपरिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र कोरबा, वन मण्डल कोरबा

पेड़ों को न काटें न काटने दें।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग छत्तीसगढ़ शासन
वनमण्डल कोरबा, जिला-कोरबा

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक युधिष्ठिर कुमार राजवाड़े द्वारा मे. डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, नर्मदा कोल्ड्रिंक के पास बिलासपुर से मुद्रित कर प्रेस क्लब भवन के सामने रिकाण्डो रोड कोरबा से प्रकाशित संपादक युधिष्ठिर कुमार राजवाड़े मो.नं.-98266-47851 आरएनआई नंबर CHHHIN/2010/47078 Email :-divyaakash.news@gmail.com